



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1]  
No. 1]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 2, 1985/पौष 12, 1906  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 2, 1985/PAUSA 12, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह तल्लग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

## उद्योग मंत्रालय

(भारो उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1984

### अधिसूचना

का०आ० 1(अ) :—मोटर गाड़ी उपकर नियम, 1984 का प्रारूप, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (भारो उद्योग विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 932(अ) तारीख 26-12-1983 के साथ भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (ii) तारीख 17 मई, 1984 में प्रकाशित किया गया था। इसके द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाला राजपत्र जनता को उपलब्ध कराया गया था, साठ दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे ;

और उक्त राजपत्र जनता को 11 जून, 1984 को उपलब्ध कराया गया था ;

आर उक्त प्रस्ताव पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अब अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटर गाड़ी उपकर नियम, 1984 है।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) “अधिनियम” से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) अभिप्रेत है ;

(ख) “मोटर गाड़ी” से अभिप्रेत है मोटर कार, बसें, ट्रक, जीप प्रकार के यान, वेन, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड और सभी अन्य मोटर गाड़ियां, जो अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्षक 7 “परिवहन” के उपशीर्षक (5) के अन्तर्गत आती हैं ;

(ग) “उपकर” से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारो उद्योग विभाग की अधिसूचना सं० का०आ० 932(अ) तारीख 28-12-83 के निबन्धनों के अनुसार उद्ग्रहीत और संग्रहीत उपकरण अभिप्रेत है ;

- (घ) "कलक्टर" से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर अभिप्रेत है और इसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपर कलक्टर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उप कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक कलक्टर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक सम्मिलित हैं ;
- (ङ) "विकास परिषद्" से अधिनियम की धारा 6 के अधीन स्थापित मोटरगाड़ी और सहवृद्ध उद्योग विकास परिषद् अभिप्रेत है ;
- (च) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम या नियमों में हैं ।

3. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों का लागू होना—इन नियमों में अन्यथा उपबंधित न सिवाय, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और उसके अधीन बनाये गये नियमों, जिनमें वे भी सम्मिलित हैं जो शुल्क के प्रतिदाय से संबंधित हैं, उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में वहां तक लागू होंगे जहां तक वे उस अधिनियम और नियमों के अधीन मोटर गाड़ियों के विनिर्माण पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

4. विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना—(1) प्रत्येक विनिर्माता, कलक्टर और विकास परिषद् के समक्ष प्रत्येक मास की दस-तारीख को या उसके पूर्व, पूर्ववर्ती मास के दौरान अपने उपक्रम में विनिर्मित या उत्पादित और वहां से हटाए गए मोटर गाड़ियों की सबों के सभी स्टॉक को विवरण, इन नियमों के उपाबंध में विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रस्तुत करेगा ।

(2) यदि कोई विनिर्माता उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करना है जिसके बारे में कलक्टर या विकास परिषद् को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह ठीक नहीं है या त्रुटिपूर्ण है तो कलक्टर, विनिर्माता से उसके द्वारा विनिर्मित या उत्पादित मोटर गाड़ियों

से संबंधित सभी या किन्हीं लेखाओं को प्रस्तुत करने को उससे अपेक्षा करते हुए सूचना तामील कर सकेगा ।

5. उपकर के आगम :—उपकर के आगम प्रथमतः "038—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क—वस्तु मोटर गाड़ियों पर उपकर" शीर्ष के अधीन भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा, और केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किये जाने के पश्चात्, विकास आगम को उतनी राशि दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।

6. खाता खोलना :—उपनियम 5 के अधीन विकास परिषद् द्वारा एक रकम, भारतीय स्टेट बैंक के खाते में रखी जाएगी ।

7. विकास परिषद् के लेखे :—(1) विकास परिषद्, नियम 5 के अधीन अपने द्वारा प्राप्त रकम से संबंधित उचित लेखा बनाए रखेगा ।

(2) प्रत्येक विनियम वर्ष के लिए लेखाओं का संपरीक्षित विवरण और उसके संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ।

8. विकास परिषद् का बजट प्राक्कलन :

(1) विकास परिषद्, प्रत्येक वर्ष आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा और उसे मंजूरी के लिये केन्द्रीय सरकार को उस तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) जब तक केन्द्रीय सरकार बजट को मंजूरी नहीं दे देती है तब तक कोई भी व्यय उपगन नहीं किया जाएगा ।

(3) बजट ऐसे अनुदेशों के अनुसार तैयार किया जायेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं ।

9. विहित प्रशासनिक व्यय—विकास परिषद्, नियम 5 के अधीन अपने द्वारा प्राप्त रकम के दो प्रतिशत से अधिक राशि का उपयोग, कार्यालय स्थापन और उपकरण, लेखन सामग्री, डाक महसूल, टेलीफोन, तार, टेलिक्स सचिवालय में नियोजित कर्मचारियों की मजदूरी और भत्तों, सदस्यों के यात्रा और दैनिक महे व्यय, और परिषद् के अधिवेशन करने से संबंधित व्यय पूरा करने के लिए कर सकेगी ।

#### उपाबंध

(नियम 4 देखिए)

मोटर गाड़ी उपकर नियम, 1934 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विवरणी का प्राक्क

..... को समाप्त होने वाला मास .....

कारखाने का नाम .....

पता .....

उपकर के अधीन रहते हुए माल का आदि अतिशेष		उपकर के अधीन रहते हुए विनिर्मित माल		उपकर के अधीन हटाए गए माल	
वर्णन	मात्रा	वर्णन	मात्रा	वर्णन	मात्रा
1	2	3	4	5	6
अन्त अतिशेष					
वर्णन	मात्रा	टिप्पणी			
7	8	9			

मैं/ हम यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मैंने / हमने ऊपर दर्शात विशिष्टियों का अपने/हमारे कारखाने के अभिलेखों और बहियों से मिलान कर लिया है और वे, जहां तक मैं/ हम अभिनिश्चित करता हूँ/ करते हैं, सही और पूर्ण हैं ।

तारीख .....

विनिर्माता के हस्ताक्षर

[एफ. सं. 8(8)/83- ए ई आई (i)]

के. एस. वैस, संयुक्त सचिव,

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 29th December, 1984

## NOTIFICATION

**S.O. 1 (E):**—Whereas the draft of the Automobile Cess Rules, 1984 was published in the Gazette of India Extraordinary Part-II Section 3—Sub-section (ii), dated the 17th May, 1984, with the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Heavy Industry) No. S.O. 932(E), dated the 28th December, 1983, as required by sub-section (1) of the Section 30 of the Industries (Development and Regulation) act, 1951 (65 of 1951), for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within sixty days from the date on which the Gazette containing the said notification was made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 11th June, 1984;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and regulation) act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title :—These rules may be called the Automobile Cess Rules, 1984.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (a) 'Act' means the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951);
- (b) 'Automobile' means motor cars, buses, trucks, jeep type vehicles, vans, scooters, motorcycles, mopeds, and all other automobiles covered under the sub-heading (5) of heading 7 'Transportation' of the First Schedule to the Act;
- (c) 'Cess' means the cess levied and collected in terms of notification No. S.O. 932 (E), dated 28-12-1983 of Department of Heavy Industry issued under sub-section (1) of section 9 of the Act;
- (d) 'Collector' means the Collector of Central Excise and includes the Additional Collector of Central Excise, the Deputy Collector of Central Excise, Assistant Collector of Central Excise and Superintendent of Central Excise;
- (e) 'Development Council' means the Developments Council for Automobile and Allied Industries established under Section 6 of the act;
- (f) words and expressions used herein and not defined but defined in the Central Excises and Salt act, 1944 (1 of 1944) or the rules made thereunder, shall have the meaning respectively assigned to them in that act or the rules.

3. Application of Central Excises and Salt act and the rules made thereunder.—Save as otherwise provided in these

rules, the provisions of the Central Excises and Salt act, 1944 (1 of 1944) and the rules made thereunder including those relating to refund of duty, shall, so far as may, apply in relation to the levy and collection of the cess as they apply in relation to the levy and collection of the duty of excise on manufacture of automobiles under the act and the rules.

4. Submission of returns.—(1) Every manufacturer shall submit to the Collector and to the Development Council on or before the 10th of every month a return in the Form specified in the annexure to these rules of all stocks of items of automobiles manufactured or produced in, and removed from his under taking during the previous month.

(2) If any manufacturer fails to furnish the return within the date specified in sub-rule (1) or furnishes a return which the Collector or the Development Council has reason to believe is incorrect or defective, the Collector may serve notice on the manufacturer calling upon him to produce all or any of his accounts relating to the automobiles manufactured or produced by him.

5. Proceeds of the cess.—The proceeds of the cess shall first be credited to the Consolidated Fund of India under the head '038—Union Excise Duties—Cess on Commodities Automobiles', and the Central Government may after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, hand over to the Development Council such sums as it may consider necessary from out of such proceeds after deducting therefrom the cost of collection.

6. Opening of Accounts.—The amount received by the Development Council under Rule 5 shall be kept in an account with the State Bank of India.

7. Accounts of the Development Council.—(1) The Development Council shall maintain proper accounts relating to the amount received by it under Rule 5.

(2) The audited statement of accounts for every financial year, together with the auditor's report thereon, shall be submitted to the Central Government.

8. Budget Estimates of the Development Council.—(1) The Development Council shall in each year prepare a budget for the ensuing financial year and submit the same for sanction to the Central Government on or before such date as may be specified by the Central Government.

(2) No expenditure shall be incurred until the budget is sanctioned by the Central Government.

(3) The budget shall be prepared in accordance with such instructions as may be issued from time to time by the Central Government.

9. Prescribed administrative expenses.—The Development council may utilise a sum, not exceeding 2 per cent of the amount received by it under Rule 5, to meet its expenses on account of office establishment and equipment, stationery, postage, telephones, telegrams, teléx, wages and allowances of staff employed in the secretariat travel and daily allowance of members, and expenditure connected with holding of Council meetings.

(See Rule—4)

Address.....

[F. No. 8(8)/83-AEI(T)]  
K.S. BAINS, Jt. Secy.